EDITORIAL

National Assets Monetization Pipeline

Assets monetisation and privatisation are the two key focus areas of the 2021-22 budget. The mechanism of privatisation is at top priority of the Central Govt and now the Govt has adopted a new system to hand over the entire core public assets to private national and international Corporates. The idea of the Govt is to hand over the Indian economy to Private Corporates. This new formula of privatisation has named as National assets, Monetisation pipeline. Earlier, the pipe lines were constructed for water supply, drainage etc. The petroleum pipe lines were also have been erected in several routs of the country to supply the petroleum products from one city to another at far distance. Now the Govt. has invented such a pipeline from through which public assets will how sharply towards the lap of private capitalists and Corporates. The Govt. has decided to sell the assets of Nation with sugar quoted word monetisation and the Hon'ble finance Minister explained that the assets will not be sold but it will be leased to earn a huge revenue to revamp new infrastructure and it will bring the sinking economic condition of country out of critical situation. But this privatisation or monetisation will badly effect upon the working class and common people of the country.

The BSNL optical Fiber Cable and 14300 mobile towers are also listed for the monetisation through which the Govt. has decided to earn 40,000 crore rupees. The BSNL workers have opposed this move of the Govt. through a strong and massive demonstration throughout the country under the banner of NFTE (BSNL). The assets of almost all the public assets of each sector have been listed to monetise such as coal, Insurance, Banking etc. to collect a huge amount, the Govt. has decided to handover almost all the infrastructural assets which has been built up by public funds over past 75 years to private hands. This will effect the lively hood of workers as the job security will not continue in Private entity and the cost of products will be raised to earn more profit by the Corporates. This will increase the burden on the people through reckless increase in user changes.

The working class in every sector are agitating against this anti workers and anti people move of the Govt.

The 10 Trade union centres of the country along with several independent Federations organised a convention on 11th November 2021 at Jantar Mantar Road, New Delhi and has decided to fight against the policy of the Govt. Declaration was passed unanimously to conduct a massive demonstration on 26th November, 2021 in the country and two days strike in budget session of 2022-23.

When direct privatisation is being resisted the working class, the Govt .has applied a new Technique to privatise all the Govt. departments and PSUs through entry of contractorisation and out sourcing of the production work and providing services.

In our BSNL also the same Technique is being applied and the maintenance works have been handed over to Private vendors in name of cluster policy and the provisioning of FTTH and other sales and marketing works are also given to the private contractor. Now the management has in-

troduced an apprentice System to appoint Diploma engineers for sales and marketing and to meet the other works of company. Thus, the BSNL management also applying the policy of the Govt. to isolate the remaining employees of Post VRS and hand over all the systems in the hand of private vendors. The restructuring of organisational setup and man power is going to be completed through which it is clear that the regular employment in company is impossible in future. Even promotional aspects are in dark in future.

The situation has been warranted that the workers should unitedly fought against the anti workers policy of the management and brought the happiness to the working classes we should learn the lesson from farmers struggle also, that how they maintained their tolerance for a long year and continued their struggle to force the Govt. to withdraw the three farmers bills imposed by the Govt. against the will of the farmers. The victory of farmers is a historic one. NFTE–BSNL salute the brave farmers and congratulates one and all.

It is also fact that we the working people cannot sit on Dharna continuously for long time, but even a demonstration with total unity can bring some better result. Ours is a democratic country and as peaceful protest is our right. The unity is only way to save our bread provider BSNL and to protect the interest of employees. Let us be unite and move forward to protest the anti workers and anti PSU policy of the Govt.

Workers Unity Zindabad.

संपादकीय

राष्ट्रीय संपदा मुद्रीकरण नलतंत्र (पाइपलाइन)

वर्ष 2021–22 के बजट का मुख्य आकर्षण मुद्रीकरण एवं निजीकरण था। निजीकरण की तकनीक सरकार की उच्च प्राथमिकता बन चुकी हैं सरकार ने सभी जन संपदाओं को देशी एवं विदेशी निगमित घरानों को सौंपने की नीति धारण कर चुकी है। सरकार का विचार राष्ट्रीय अर्थतंत्र को निजी हाथों में सौंप देने का है। सरकार ने नये निजीकरण के नये सूत्र के रूप में राष्ट्रीय संपदा मुद्रीकरण नलतंत्र का इजाद किया है। पहले नलतंत्र पानी को तेजी से प्रवाहित करने या गंदे जल के प्रवाह के लिए बनाई जाती थी। पेट्रोलियम उत्पाद को एक शहर से किसी दूसरे दूरस्थ शहर में पहुंचाने के लिए नलतंत्र की व्यवस्था बनाई जाती थी परंतु अब सरकार ने एक ऐसे नलतंत्र का अविष्कार किया है जिसके द्वारा समस्त राष्ट्रीय जन संपदा तेजी से प्रवाहित होकर धन्नासेठों एवं खानगी निगमी घरानों की गोद में पहुंच जायेगी। मुद्रीकरण के मधुर शब्द का इस्तेमाल करके सरकार सभी राष्ट्रीय संपदा को बेच देना चाहती है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि नलतंत्र के द्वारा संपदा को बेचा नहीं जायेगा अपितु इसे बंधक रखा जायेगा जिससे राष्ट्रीय परिसंपदा का पुननिर्माण की व्यवस्था की जायेगी।

यह मुद्रीकरण तथा निजीकरण राष्ट्रीय मजदूर वर्ग एवं आम जनता के लिए घातक है। बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर केबुल तथा 14300 मोबाइल टॉवरों को भी मुद्रीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बीएसएनएल कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीएसएनएल कर्मचारियों ने 27 नवंबर 2021 को इसके विरूद्ध समस्त राष्ट्रीय पैमाने पर एनएफटीई के आह्वान पर रोष पूर्ण प्रदर्शन करके विरोध जताया है। तकरीबन सभी इकाई के राष्ट्रीय संपदा को बेचने की योजना बनाई गई है, जैसे रेल, हाइवे, पेट्रोलियम, कोयला, पावर, बीमा एवं बैंकिंग आदि। सरकार ने संपदाओं को दृढ़ विचार बनाया है जो जनजीवन को तबाह कर सकती है। ये संपदा जनता के गाढ़े कमाई के पैसों से पिछले 75 वर्षों में निर्मित की गई थी। इस प्रक्रिया से कार्यकारियों की नौकरी निजी हाथों में चली जायेगी जो सुरक्षित नहीं रहेगी। निजी धन्नासेठ अधिक मुनाफा बटोरने के चक्कर में उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि करेंगे जिससे आम जनता की जिन्दगी दूभर हो जायेगी वर्तमान में सभी क्षेत्रों के कर्मचारी एवं मजदूर संघर्षरत हैं।

दस राष्ट्रीय श्रमिक संघों एवं स्वतंत्र महासंघों के प्रतिनिधियों ने 11 नवम्बर 2021 को दिल्ली के जंतर– मंतर रोड पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया था। कन्वेंशन में हजारों मजदूरों एवं सेवा क्षेत्र के लोग उपस्थित होकर एक घोषणा को अनुमोदित किया जिसके तहत पूर्ण राष्ट्रीय पैमाने पर 26 नवम्बर 2021 को रोषपूर्ण प्रदर्शन एवं 2021–22 के बजट क्षेत्र में संपूर्ण हड़ताल आयोजित करने का निर्णय है।

जब सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निजीकरण का कर्मचारियों, मजदूरों एवं देश की जनता ने विरोध के द्वारा रुकावट पैदा करते रहे, तो सरकार ने नया रास्ता अपनाया और सभी सरकारी विभागों एवं लोक उपक्रमों में ठेकेदारी प्रथा के द्वारा उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र को कार्य संपादन की व्यवस्था कर रही है। हमारे बी.एस.एन.एल के अर्न्तगत भी इसी तकनीक के आधार पर अनुरक्षण के समस्त कार्य निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है।

कलस्टर एवं टी.पी.आई.के द्वारा समस्त एफ.टी.टी.एच एवं टेलीफोन, ब्राडबैंड, लीज्ड लाइन सहित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों को भी निजी संघों में सौंप दिया गया है। अभी प्रबंधन ने अप्रेंटिस की भर्ती कर ब्रिकी एवं विपणन का कार्य करने की व्यवस्था बनायी है। सरकार की नीतियों के नक्शे कदम चलकर बी.एस.एन.एल प्रबंधन वीआरएस के

उपरान्त बचे कर्मचारियों को कार्य विहिन बनाकर कुंठित करने की व्यवस्था बना रही है।

अभी हाल में रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर संगठित ढ़ांचे में बेतरतीब फेर–बदल करते हुए कार्यबल की संख्या में भारी कमी दर्ज किया गया है जिनमें एक्जीक्यूटिव एवं नान एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वरिष्ठ अधर में लटक रहे है।

स्थिति भयावह बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब जब–जब सत्ता के द्वारा कामगारों पर प्रहार हुए हैं, कामगारों ने एकता के बल पर सत्ता के कर्मचारी विरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों पर प्रहार करते हुए अच्छे प्रतिफल के साथ आगे बढ़ते आये हैं।

हमें कृषक आंदोलन से भी सीख लेने की जरुरत है। किसानों ने पूर्ण धैर्य के साथ लंबे संघर्ष के माध्यम से सरकार को झुकने पर मजबूर किया तथा तीन अनचाहे कृषि कानूनों की वापसी कराई। हम इस तरह के लम्बे संघर्ष नहीं कर सकते परन्तु हम पूर्ण एकजुटता के साथ अगर एक प्रदर्शन का भी आयोजन करें तो हम एक असरदार प्रभाव ला सकते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हैं और शांतिपूर्ण विरोध द्वारा अपनी समस्याओं को उजागर करने का हमें संवैधानिक हक है। अतएव आइये हम पूर्ण एकजुट होकर अपने अन्नदाता कम्पनी बी.एस.एन.एफ की रक्षा करते हुए समस्त कर्मचारियों की हित रक्षा कर सकते हैं।

कर्मचारी एकता जिन्दाबाद।